हरित भारत मिशन की लेखापरीक्षा: पौधरोपण से पारिस्थितिक परिणाम तक

समाचार संदर्भ: 12 अगस्त 2026 को संसद में रिपोर्ट | पर्यावरण • जवाबदेही | GS-II/III

कितने पौधे लगाए और कितना खर्च हुआ, यह शुरुआत है। वन की गुणवत्ता, जीवित पौधे, स्थानीय जैव विविधता और समुदाय को हुए लाभ परिणाम की बेहतर कसौटियाँ हैं।

खबरों में क्यों

हरित भारत मिशन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 4, 2026 को 12 अगस्त 2026 को संसद में रखा गया। 13 अगस्त की आधिकारिक विज्ञप्ति ने इसकी जानकारी दी। लेखापरीक्षा ने 2015–16 से 2024–25 की अवधि में 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मिशन के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी की जाँच की। नया संदर्भ लेखापरीक्षा है, मिशन का नया शुभारंभ नहीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा क्या देखती है?

यह सार्वजनिक कार्यक्रम के संसाधनों और परिणामों की जाँच है। केवल भुगतान के कागज पर्याप्त नहीं होते; योजना अपने उद्देश्यों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुँची, यह भी प्रश्न है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके नमूने, अवधि और लक्ष्य के संदर्भ में पढ़ना चाहिए।

मुख्य तथ्य

समन्वय की कमी: मिशन में अन्य वनरोपण योजनाओं और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से संसाधन तथा गतिविधियाँ जोड़ने की अपेक्षा थी। CAG ने इस अभिसरण, समय पर योजनाओं की मंजूरी और निगरानी में कमियाँ बताईं।

लक्ष्य का सही अर्थ: रिपोर्ट में मिशन के अंतर्गत वनावरण बढ़ाने के 1.4 मिलियन हेक्टेयर लक्ष्य के सामने 0.03409 मिलियन हेक्टेयर उपलब्धि बताई गई, यानी 97.57 प्रतिशत कमी। यह मिशन के विशिष्ट लक्ष्य से अंतर है; देश के 97.57 प्रतिशत वन समाप्त होने का आँकड़ा नहीं।

भौगोलिक सत्यापन: लेखापरीक्षा ने कार्यस्थलों की स्थान-संबंधी फाइलों और रिपोर्ट की गई उपलब्धियों के सत्यापन में समस्याएँ बताईं। उपग्रह या GIS जाँच के साथ जमीन पर सत्यापन भी जरूरी है। नमूना स्थलों के निष्कर्ष सभी भारतीय वनों का निष्कर्ष नहीं हैं।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

वित्त और पारिस्थितिकी को साथ क्यों पढ़ें?

समय का असर: रोपण की ऋतु निकलने के बाद धन मिलने से लागत और पौधों के जीवित रहने की संभावना प्रभावित हो सकती है। निधि का समय, केवल कुल राशि जितना महत्त्वपूर्ण है।

उपयुक्त स्थान और प्रजाति: वन बहाली हर जगह एक जैसा पौधरोपण नहीं है। जलवायु संवेदनशीलता, स्थानीय प्रजातियाँ और पारिस्थितिकी के आधार पर स्थान तथा उपाय चुने जाने चाहिए।

समुदाय और निगरानी: स्थानीय लोगों की जरूरत, ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण और सार्वजनिक सूचना गलत रिपोर्टिंग पहचानने तथा संरक्षण में भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

विश्लेषण और आगे की राह

योजना में अलग-अलग संस्थाओं की जिम्मेदारी, संसाधन का वास्तविक स्रोत और काम का समय पहले स्पष्ट होना चाहिए। अभिसरण का अर्थ अन्य योजना की राशि स्वतः उपलब्ध मान लेना नहीं है। स्थल चयन से रखरखाव तक निरंतरता हो और क्षेत्रफल की दोहरी गिनती रोकी जाए। स्वतंत्र भौगोलिक सत्यापन को स्थानीय जाँच से जोड़ें। परिणाम में जीवित पौधे, वन की गुणवत्ता, जल-संरक्षण, जैव विविधता और आजीविका शामिल हों। लेखापरीक्षा कमियाँ बताती है; उसके बाद सुधार की कार्रवाई और आगे के परिणाम भी अलग से जाँचे जाने चाहिए।

अवधारणा में अंतर

वनावरण बढ़ाना, मौजूदा वन की गुणवत्ता सुधारना और कार्बन अवशोषण मापना अलग परिणाम हैं। किसी एक के लिए घोषित उपलब्धि दूसरे की स्वतः पुष्टि नहीं है।

मेंस दृष्टि

GS-II/III में CAG, सार्वजनिक योजना और पर्यावरणीय शासन। उत्तर में धन की कमी के साथ नियोजन, संस्थागत समन्वय और सत्यापन की समस्या जोड़ें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

पर्यावरणीय कार्यक्रमों की सफलता को व्यय और रोपित पौधों की संख्या से आगे बढ़कर मापना आवश्यक है। हरित भारत मिशन की लेखापरीक्षा के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: पर्यावरणीय योजना में व्यय और पौधों की संख्या गतिविधि के संकेतक हैं, पारिस्थितिक सफलता की पूरी कसौटी नहीं। हरित भारत मिशन की निष्पादन लेखापरीक्षा के आधार पर यह अंतर रखें।

मुख्य भाग में: CAG द्वारा बताए अभिसरण, मंजूरी और निगरानी के अंतर को समझाएँ। समय पर धन, रोपण ऋतु, स्थानीय प्रजाति और स्थल की उपयुक्तता को परिणाम से जोड़ें। GIS और स्थल-फाइलों की स्वतंत्र जाँच के साथ जमीन पर सत्यापन, ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण और दोहरी गिनती रोकना जरूरी है। जीवित पौधे, वन गुणवत्ता, जल-संरक्षण, जैव विविधता और आजीविका मापें; नमूना तथा अवधि की सीमा रखें।

निष्कर्ष में: लेखापरीक्षा के बाद जिम्मेदारी और सुधार के परिणाम भी जाँचे जाएँ। मिशन के विशिष्ट वनावरण लक्ष्य से 97.57 प्रतिशत कमी को भारत के कुल वनों की उतनी हानि न समझें; बहाली का मूल्य वास्तविक पारिस्थितिक लाभ से तय हो।

स्रोत

- CAG की मूल रिपोर्ट संख्या 4, 2026
- रिपोर्ट की प्रस्तुति और मुख्य निष्कर्ष, 13 अगस्त 2026

याद रखें: लक्ष्य से 97.57 प्रतिशत कमी, भारत के कुल वन क्षेत्र में उतनी कमी नहीं है।